

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों, सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है। यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देते हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियां सीएजी द्वारा की जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था सम्बन्धित अधिनियमों जिनके तहत ये निगम स्थापित किये गए हैं, के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है। सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं, अध्याय-I में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं का परिचय सम्मिलित है। अध्याय-II में 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' एवं 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा के परिणामों एवं सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं। अध्याय-III में विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2020-21 में की गयी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए एवं वे जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु उनका उल्लेख गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2020-21 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बन्धित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।